उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 548/ 2022

मनीष पंवार .... पुनरीक्षणवादी

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .... प्रत्य8र्थी

उपस्थित:
श्री तपन सिंह, पुनरीक्षणवादी के अधिवक्ता
श्री पंकज कुमार जोशी, शासकीय ब्रीफ होल्डर

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठानी, (मौखिक) तत्कालिक पुनरीक्षण को निम्नलिखित के विरुद्ध प्राथमिकता दी जाती है:-

(i) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिहरी की न्यायालय द्वारा 2015 के आपराधिक मामला संख्या 196, राज्य बनाम मनीष पंवार में निर्णय और आदेश दिनांक 26.04.2022 को पारित किया गया। इसके द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") की धारा 3 के साथ धारा 7 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और पांच साल की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है और 20,000 रुपये के जुर्माना और अग्रिम शर्त के साथ कि जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहने पर पुनरीक्षणकर्ता को एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(ii) मनीष पंवार बनाम उत्तराखंड राज्य 2022 की आपराधिक अपील संख्या 13 में निर्णय और आदेश दिनांक 06.09.2022 को पारित किया गया। इसके द्वारा, मामले में पारित 26.04.2022 के निर्णय और आदेश को मान्य ठहराया गया है।

2. विवाद को समर्थित करने वाले आवश्यक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी पीडब्ल्यू-1 किशन सिंह भंडारी को बताया गया कि चमियाला में कोई अनाधिकृत रूप से डीजल बेच रहा है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे मामले को देखने के लिए निर्देशित किया गया था। 23.03.2015

को पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी ने पीडब्ल्यू 3 हेत राम ममगाईं, राजस्व उप-निरीक्षक, पीडब्ल्यू 4 गंभीर सिंह बिष्ट, खाद्य गोदाम के चौकीदार और पीडब्ल्यू 5 मनोज बड़थ्वाल, आपूर्ति निरीक्षक के साथ उस स्थान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय पीडब्ल्यू 6 सोबन सिंह और सतेय सिंह भी टीम में सम्मिलित हुए। पेट्रोल पंप की चाबी पीडब्ल्यू 2 सतेय सिंह ने सौंपी थी। पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी ने अन्य साक्षियों की मौजूदगी में पंप से तीन नमूने लिए और उसे जब्त कर लिया। एक जब्ती ज्ञापन प्रदर्श क1 तैयार किया गया था, जिस पर पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी, पीडब्ल्यू 3 हेत राम ममगाईं, पीडब्ल्यू 4 गंभीर सिंह बिष्ट और पीडब्ल्यू 5 मनोज बड़थ्वाल ने हस्ताक्षर किए थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पेट्रोल पंप पर सेल्समैन पीडब्ल्यू 6 सोबन सिंह और सतेय सिंह पंवार ने जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

3. इसके बाद पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी ने जिलाधिकारी को सूचित किया और प्रदर्श क 3 रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके आधार पर 27.03.2015 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना की गई। पंप से लिए गए डीजल के नमूने पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी द्वारा 24.03.2015 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजे गए थे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की प्रयोगशाला में उनकी जांच की गई। पीडब्ल्यू 9 अनूप सिंह रावत ने रिपोर्ट प्रदर्श क 7 को साबित किया, जिसके अनुसार नमूने हाई स्पीड डीजल के अनुरूप हैं। विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। 09.02.2021 को, पुनरीक्षणकर्ता को बायोडीजल और हाई स्पीड डीजल के भंडारण और बिक्री के लिए अधिनियम की धारा 3 और 7 के अंतर्गत आरोपित किया गया था। पुनरीक्षणकर्ता ने अपना दोषी होने का अभिवाक नहीं किया और विचारण करने की मांग की।

4. अपने मामले को साबित करने के क्रम में, अभियोजन पक्ष ने ग्यारह साक्षियों की परीक्षा की, जिनमें पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी, पीडब्ल्यू 2 सुंदर सिंह रावत, पीडब्ल्यू 3 हेतराम ममगाईं, पीडब्ल्यू 4 गंभीर सिंह बिष्ट, पीडब्ल्यू 5 मनोज बड़थ्वाल, पीडब्ल्यू 6 सोबन सिंह रावत, पीडब्ल्यू 7 श्रीमती अंजू देवी, पीडब्ल्यू 8 मो. अकरम, पीडब्ल्यू9 अनूप सिंह रावत, पीडब्ल्यू 10 प्रदीप कुमार और पीडब्ल्यू 11 संदीप बंसल।

5. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद, पुनरीक्षणकर्ता से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("संहिता") की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षा की गई। उनके अनुसार, साक्षियों ने झूठे और गलत बयान दिये है। उसने कोई अपराध नहीं किया है।

6. जैसा कि एतदपूर्व अभिकथित है, इस मामले में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेशों द्वारा, पुनरीक्षणकर्ता को दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। दिनांक 26.04.2022 के निर्णय और आदेश को अपील में असफल रूप से चुनौती दी गई है। इसलिए, पुनरीक्षण दायर किया गया।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

8. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कई निवेदन दिए गए। उनके अनुसार, अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि 23.03.2015 को जो भी नमूने लिए गए थे, वे हाई स्पीड डीजल के थे। यह तर्क दिया जाता है कि पीडब्ल्यू 9 अनूप सिंह रावत ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श क7 को एक दस्तावेज अर्थात 5 ए / 56 पर आधारित किया, जिसे साबित नहीं किया गया है, जिस पर कोई हस्ताक्षर नहीं है और जिसमें यह दर्ज नहीं है कि नमूना हाई स्पीड डीजल का था। विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन में निम्नलिखित बिंदुओं को भी उठाया:

a. नमूने 10 दिनों के भीतर भेजे जाने थे। मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) आदेश, 1998 का उल्लेख किया गया है।
b. इस बात का कोई अभिलेख नहीं है कि नमूने कब भेजे गए थे।
c. संहिता की धारा 100 (4) का कोई अनुपालन नहीं किया गया है।
d. पेट्रोल पंप को जब्त किए जाने के समय स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है।
e. पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी का बयान अन्य साक्षियों के कथनों के साथ सारभूत विवरण में विरोधाभासी है।
f. पीडब्ल्यू 10 प्रदीप कुमार, जो विवेचना अधिकारी हैं, ने पुष्टि की है कि उन्होंने नमूने कभी नहीं देखे। नमूने कभी न्न्यायायल में पेश नहीं किए गए। यहां तक कि सील भी कभी न्यायालय के सामने पेश नहीं की गई। यह अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह उत्पन्न करता है।

9. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि वास्तव में, आक्षेपित निर्णय और आदेशों में गंभीर त्रुटियां और अवैधताएं हैं, जो दोषसिद्धि को दूषित करती हैं। इसलिए, पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने और सुने जाने के योग्य है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि चूंकि यह मामला प्रवेश चरण में है, इसलिए पुनरीक्षणकर्ता के पास मामले की कोई पेपर बुक नहीं है, इसलिए, मामले को स्वीकार किया जा सकता है, और उसके बाद, इसे अंतिम रूप से विस्तार से सुना जा सकता है।

10. विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में कोई अवैधता नहीं है।

11. संहिता की धारा 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण का प्रावधान निम्नानुसार है:

> (1) उच्च न्यायालय या कोई सेशन न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्यवाही के अभिलेख को, किसी अभिलिखित या पारित किए गए निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अवर न्यायालय की किन्हीं कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है और ऐसा अभिलेख मागाते समय निदेश दे सकता है कि अभिलेख की परीक्षा लम्बित रहने तक किसी दण्डादेश का

निष्पादन निलम्बित किया जाए और यदि अभियुक्त परिरोध में है तो उसे जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर छोड़ दिया जाए।

स्पष्टीकरण - सभी मजिस्ट्रेट, चाहे वे कार्यपालक हो या न्यायिक और चाहे वे आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग कर रहै हो, या अपीलीय अधिकारिता का, इस उपधारा के और धारा 398 के प्रयोनों के लिए सेशन न्यायाधीश अवर समझे जाएंगे।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग किसी अपील, जांच विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतवर्ती आदेश की बाबत नहीं किया जाएगा।

(3) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन आवेदन या तो उच्च न्यायालय को या सेशन न्यायाधीश को किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा कोई और आवेदन उनमें से दूसरे के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

12. उपर्युक्त का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनरीक्षण का दायरा किसी भी निष्कर्ष की शुद्धता, वैधता और औचित्य की जांच करने की सीमा तक सीमित है। पुनरीक्षण याचिका दायर करना किसी व्यक्ति का वैधानिक अधिकार नहीं है। यह मूल रूप से उपलब्ध एक प्रकार की पात्रता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की एक श्रेणी में पुनरीक्षण के दायरे पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। अकालू अहीर और अन्य बनाम रामदेव राम (1973) 2 एससीसी 583 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकित किया है कि "उच्च न्यायालय में इस शक्ति को निहित इसलिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय, आपराधिक न्यायशास्त्र के मान्यता प्राप्त नियमों के अनुरूप हो और अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को पार न करे या विधि द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्ति का दुरुपयोग न करे । एक सामान्य नियम के रूप में, सीआरपीसी की धारा 435 और 439 की व्यापक भाषा के बावजूद भी यह शक्ति विधिक अशक्तता और न्याय की विफलता के अभाव में तथ्य के निष्कर्षों के साथ हस्तक्षेप पर विचार नहीं करती है। निश्चित रूप से, इस शक्ति का प्रयोग ऐसे नहीं होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का खण्डन करे जैसा कि तब होता है जब पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने की आड़ में, उच्च न्यायालय वैधानिक निषेध के रूप में अपील की शक्ति का उपयोग करता है।

13. दुलीचंद बनाम दिल्ली प्रशासन, (1975) 4 एससीसी 649 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोलित कि "उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में एक प्रतिबंधित प्रकृति के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है इसलिए, यह निर्धारित करने के उद्देश्य से कि क्या विद्वान मजिस्ट्रेट और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्राप्त तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष सही था, या नही साक्ष्यों की पुन: समीक्षा से इनकार करना न्यायोचित होगा ।

14. महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद और अन्य (2004) 7 एससीसी 659 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकित किया है कि "प्रारंभ में पुनरीक्षण स्तर पर सभी साक्ष्यो का सूक्ष्मता से पुनः परीक्षण करते हुए, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश उस आत्म-नियंत्रण से पूर्णतः अनभिज्ञ थे जो उन्हें धारा 397 सीआरपीसी के अंतर्गत पुनरीक्षण में प्रयोग करने की आवश्यकता थी। अभियुक्तगण की ओर से, इस न्यायालय के निर्णय राम बृक्ष सिंह बनाम अंबिका यादव, (2004) 7 एससीसी 665 पर विश्वास किया गया है, जिस मामले में हम में से न्यायमूर्ति सभरवाल भी है । यही वह मामला था जिसमें उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण में हस्तक्षेप किया क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारभूत साक्ष्यो की अनदेखी की गई थी।

15. महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेश पोयारेकर (2008) 9एससीसी 475 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि "अब यह पूर्णतः स्थापित है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग असाधारण मामलों में विरलता से किया जाना चाहिए, एक पुनरीक्षण न्यायालय स्वयं को नियमित अपीलीय न्यायालय में परिवर्तित नहीं कर सकती है।

16.गिरीश कुमार सुनेजा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2017) 14 एससीसी 809 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकित किया कि "इस विषय पर हमारा निष्कर्ष यह है कि अपीलकर्ताओं के पास उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने की पात्रता (अधिकार नहीं) हो सकता है, परंतु उस पात्रता को छीना जा सकता है और किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है- ऐसी याचिका को प्रारम्भिक स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

17. वास्तव में, अमित कपूर बनाम रमेश चंदर, (2012) 9 एससीसी 460 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण के दायरे पर चर्चा की और पैरा 12 और 13 में निम्नानुसार टिप्पणी की: –

> "संहिता की धारा 397 न्यायालय को किसी मामले में की गई किसी भी कार्यवाही या आदेश की वैधता और नियमितता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से एक अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को मंगाने और जांचने की शक्ति प्रदान करती है। इस प्रावधान का उद्देश्य पेटेंट दोष या अधिकार क्षेत्र या विधि की त्रुटि को ठीक करना है। इसके लिए त्रुटि पूर्णतः स्थपित होनी चाहिए और न्यायालय के लिए ऐसे आदेशों की जांच करना उचित नहीं हो सकता है, जो कि सावधानीपूर्वक विचार किए गए है और विधि अनुसार पारित किए गए है। यदि कोई इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को देखता है, तो यह पता चलता है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को वहां लागू किया जा सकता है जहां आपत्ति के अंतर्गत निर्णय पूर्णतः गलत हैं, विधि के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है, अभिलिखित निष्कर्ष किसी सबूत पर आधारित नहीं है, सारभूत साक्ष्य की अनदेखी की गई है या न्यायिक विवेक का मनमाने ढंग से या

विकृत रूप से प्रयोग किया गया है। ये श्रेणियां संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि सिर्फ सांकेतिक हैं। प्रत्येक मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर निर्धारित करना चाहिए l

13. एक और पूर्णतः स्वीकृत मानदंड यह है कि उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और इसे नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अंतर्निहित प्रतिबंधों में से एक यह है कि यह अंतरिम या मध्यस्थ आदेश के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। न्यायालय को यह ध्यान रखना होगा कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग से प्रथम दृष्टया अन्याय नहीं होना चाहिए। जहां न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या किसी दिए गए मामले में आरोप उचित रूप से और विधि के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, तो जब तक मामला उल्लिखित श्रेणियों के भीतर नहीं आता है न्यायालय अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है । चूंकि आरोप विरचित करना भी सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाही में एक बहुत अग्रिम चरण है।

18. पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार की परिभाषित रूपरेखा के अंतर्गत, मामले की विचारण की आवश्यकता है। अधिकांशत: पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता मामलों के तथ्यात्मक बिंदुओं के संबंध में तर्क देते हैं। जैसा कि कहा गया है, यह न्यायलय, नियमित अपीलीय न्यायाल के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इस पुनरीक्षण को द्वितीय अपील नहीं माना जा सकता। पुनरीक्षण में साक्ष्य की सराहना की अनुमति नहीं है, जब तक कि निष्कर्ष उचित न हो अर्थात साक्ष्य के भार के विरुद्ध न हो या स्वीकार्य साक्ष्य को उपेक्षित न किया जाए या अस्वीकार्य साक्ष्य को विमर्श में न रखा जाए। यह तर्क दिया जा रहा है कि साक्ष्यों के अभाव में मामला साबित नहीं हुआ है। क्या "साबित" है, क्या "साबित नहीं हुआ है" और क्या "नासाबित" है, इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 ("साक्ष्य अधिनियम") की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है: –

"साबित" - कोई तथ्य साबित हुअ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व हैं।

"नासाबित" - कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं हैं।

"साबित नहीं हुआ" - कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

19. "साबित" और "नासाबित" के इस बिंदु का संबंध साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 से है, जिसमे प्रावधान है कि न्यायालय कुछ तथ्यों के अस्तित्व का अनुमान कैसे लगा सकती है। इस धारा के अनुसार, "न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकता है जो उसे लगता है कि, प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम, विशेष मामले के तथ्यों के संबंध में होने की संभावना है।

20. के पोन्नुस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य, (2001) (6) एससीसी 674 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "साबित" की अवधारणा पर चर्चा की और पैरा 27 में निम्नानुसार उल्लिखित है: –

"27. अपने तर्क के समर्थन में श्री राव ने कृष्णानंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1977) 1 एससीसी 816 के मामले में इस न्यायालय की अधिकारिता पर विश्वास किया l

1977 एससीसी (सीआरआई) 190] इस मामले में न्यायालय ने निम्नानुसार माना है: (एससीसी पीपी 830-31, पैरा 26) "यह पूर्णतः निर्धारित है कि यह दर्शित करने का भार कि कोई विशेष लेनदेन बेनामी है और अपीलकर्ता मालिक वास्तविक मालिक नहीं है, सदैव उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो ऐसा होने का दावा करता है और इस भार को एक निश्चित प्रकृति के विधिक साक्ष्य के द्वारा प्रस्तुत करके कठोरता से निर्वहन किया जाना चाहिए जो या तो सीधे तथ्यों से बेनामी को साबित करेगा या उस तथ्य के प्रति अनुमान कराने वाले यथोचित परिस्तिथियो को स्थापित करेगा। बेनामी का भाव पक्षकारों के आशय से है और अधिकांशत:, इस तरह के आशय एक मोटे पर्दे की भांति होते हैं जिन्हें आसानी से भेदा नहीं जा सकता है। परंतु लेन-देन को बेनामी बताने वाले व्यक्ति को इस तरह की कठिनाइयां उस गंभीर दायित्व से छुटकारा नहीं दिलाती हैं जो उस पर भारित है, और न ही साक्ष्य के विकल्प के रूप में केवल अनुमानों या अनुमानों की स्वीकृति को सही ठहराती हैं। केवल उन परिस्थितियों को दिखाना पर्याप्त नहीं है जो संदेह उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि न्यायालय संदेह के आधार पर निर्णय नहीं कर सकती है। इसे साक्ष्यों द्वारा स्थापित विधिक आधार पर कार्य करना होगा।

विधिक कथनों के संबंध कोई विवाद नहीं हो सकता है। यद्यपि देखते है कि "साबित" का क्या अर्थ है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 "साबित" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

एक तथ्य को तब साबित कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व हैं।

इसके अलावा, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 निम्नानुसार है:

"114. न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा - न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है।

इस प्रकार इस तथ्य को तब साबित कहा जाता है जब उसके समक्ष मामलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय इसे अस्तित्व में मानती है, या इसके अस्तित्व को इतना संभावित मानती है कि एक विवेकशील व्यक्ति को, विशेष मामले की परिस्थितियों में, इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि यह अस्तित्व में है। अपने विश्वास पर आने पर न्यायालय किसी भी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगा सकती है जो उसे लगता है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों के संबंध में घटना, मानव आचरण और सार्वजनिक और निजी व्यवसाय के प्राकृतिक पाठ्यक्रम के संबंध में होने की संभावना है।

21. चूंकि, इस तर्क के साथ यह निवेदन किया गया है कि तथ्यात्मक बिंदुओं की अवैधता ठोस है, इसलिए साक्षियों ने जो कहा है, उसकी संक्षेप में जांच करना उचित होगा।

22. पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी उस समय पर क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारी थे। उनके अनुसार, 23.03.2015 को शाम 5:00 बजे उन्हें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बताया गया कि पुनरीक्षणकर्ता अनधिकृत रूप से बायो-डीजल पंप चला रहा है। उन्हें निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। उसी दिनाक को 8:00 बजे, उन्होंने पीडब्ल्यू 3 हेत राम ममगाईं, राजस्व उप-निरीक्षक, पीडब्ल्यू 4 गंभीर सिंह बिष्ट और पीडब्ल्यू 5 मनोज बड़थ्वाल के साथ साइट का दौरा किया। पेट्रोल पंप की चाबी सतेय सिंह पंवार के पास थी। उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया, जो वह नहीं कर सके। पंप खोला गया। दो मशीनें थीं। एक मशीन में रीडिंग 000 पर दिख रही थी और दूसरी मशीन में इंडिकेशन 27.36 लीटर पेट्रोल और 55.43 लीटर डीजल दिख रहा था। भूमिगत डीजल टैंक की भी एक पैमाने से गहराई से जांच की गई। इसमें 44 अंक थे। सतेय सिंह और सोबन सिंह से डीप चेक चार्ट की मांग की गई थी। वास्तव में, सोबन सिंह इस मामले में पीडब्ल्यू6 हैं। उन्होंने चार्ट तैयार नहीं किया। तीन नमूने एल्यूमीनियम के बक्से में लिए गए थे, जिन्हें जिला आपूर्ति अधिकारी को भेज दिया

गया था। इस साक्षी ने जब्ती ज्ञापन प्रदर्श क1 को साबित कर दिया। उनकी रिपोर्ट, प्रदर्श क2 और एफआईआर प्रदर्श क3 है। पीडब्ल्यू 3 हेत राम, पीडब्ल्यू 4 गंभीर सिंह बिष्ट और पीडब्ल्यू 5 मनोज बड़थ्वाल, सभी ने पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी के बयान की पुष्टि की है जो कृत्य उसके द्वारा दिनांक 23.03.2015 को किया गया था। उन्होंने प्रदर्श क1, जब्ती ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर भी साबित कर दिए हैं।

23. एक अन्य साक्षी पीडब्ल्यू 6 सोबन सिंह रावत हैं, उन्होंने स्वीकार किया हैं कि वह मनीषबायो-डीजल पंप पर काम कर रहे थे और उसे 21.03.2022 को नियुक्त किया गया था। उसे न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में पीडब्ल्यू1 किशन सिंह भंडारी, पीडब्ल्यू3 हेत राम ममगाईं, पीडब्ल्यू4 गंभीर सिंह बिष्ट और पीडब्ल्यू5 मनोज बड़थ्वाल के बयानों का भी समर्थन किया है। उसने स्वीकार किया कि नमूने लिए गए थे। यह जब्ती के साक्षी अर्थात पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी के बयान का समर्थन करता है कि पीडब्ल्यू 6 सोबन सिंह रावत की उपस्थिति में, नमूने लिए गए थे, परंतु उसने जब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। प्रदर्श क1, जब्ती ज्ञापन का मात्र परिशीलन इसे साबित करता है।

24. पीडब्ल्यू2 सुंदर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जमीन पर यह पंप लगाया गया था। उसके अनुसार, उसके पास श्रीकोट चमियाला में कुछ जमीन है। पुनरीक्षणकर्ता ने 19.08.2014 को उससे पट्टे पर जमीन ली। एक स्टाम्प पेपर पर एक पट्टा विलेख भी निष्पादित किया गया था। उन्होंने पट्टा विलेख प्रदर्श 8ए/2 के बारे में बताया, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं। हालांकि, प्रदर्शित नहीं किया गया है, परंतु इसे निश्चित रूप से साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है क्योंकि इस साक्षी ने इस पर अपने हस्ताक्षर साबित किए हैं और कहा है कि यह पट्टा विलेख बायोडीजल पंप स्थापित करने के लिए इस भूमि के संबंध में निष्पादित किया गया था। यह दर्ज है कि भूमि खाता खतौनी नंबर 183 की है। यह एक अन्य दस्तावेज़ प्रदर्श. क 4 से जुड़ा हुआ है, जिसे पीडब्ल्यू3 हेत राम द्वारा साबित किया गया है। पीडब्ल्यू 3 के अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता हेत राम ने मनोज बायोडीजल पंप स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। पीडब्ल्यू3 हेत राम ने जांच की थी और दिनांक 13/03/2013 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार जमीन सुंदर सिंह अर्थात पीडब्ल्यू2 के नाम पर थी। इस साक्षी ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रदर्श क4 को साबित किया,जो वास्तव में पीडब्ल्यू 2 सुंदर सिंह के बयान का समर्थन करता है। इस रिपोर्ट में पीडब्ल्यू 3 हेत राम लिखते हैं कि यह जमीन खाता खतौनी नंबर 183 की है।

25. पीडब्ल्यू7 श्रीमती अंजू देवी सतेय सिंह की पत्नी हैं, जिनके पास प्रासंगिक समय पर पेट्रोल पंप की चाबी थी, जब इसकी तलाशी ली गई और जब इसे जब्त किया गया था। उसके अनुसार, पुनरीक्षणकर्ता ने उसे और उसके पति को बताया था कि वह एक बायोडीजल पंप खोलना चाहते हैं। उसके पास लाइसेंस था। वह इस साक्षी की सहायता लेना चाहता था ताकि इस उद्देश्य के लिए किसी भूमि की पहचान कर सकें।

26. पीडब्ल्यू8 मो. अकरम विवेचना अधिकारी हैं, जिन्होंने विवेचना का एक भाग किया है। उन्होंने चिक एफआईआर और जनरल डायरी प्रविष्टियों को साबित किया।

27. पीडब्ल्यू9 अनूप सिंह रावत एक महत्वपूर्ण साक्षी हैं। उनके अनुसार, उन्होंने नमूनों पर रिपोर्ट दी। इस साक्षी का कहना है कि, वास्तव में, अपनी छुट्टी के दौरान, लैब अधिकारी डॉ. केएस रेड्डी ने एक परीक्षण रिपोर्ट तैयार की थी, जो अभिलेख पर पेपर नंबर 5 क/ 56 है, इसके आधार पर, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उनके अनुसार, नमूना एचएसडी बीएस -3 था, जो हाई स्पीड डीजल (एचएसडी बीएस -3) है।

28. पीडब्ल्यू 10 प्रदीप कुमार विवेचना अधिकारी हैं। उन्होंने विवेचना के बारे में बताया है और कुछ दस्तावेजों को साबित किया है।

29. पीडब्ल्यू 11 संदीप बंसल वह व्यक्ति है, जिसने न्यायालय में कहा कि पुनरीक्षणकर्ता ने उससे दो तेल मशीनें और एक तेल भंडारण टैंक खरीदा था। उन्होंने लाल टप्पर से चमियाला तक तेल ले जाने के लिए एक टैंकर यूके07सीए0830 भी किराए पर लिया था।

30. संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपनी परीक्षा में, पुनरीक्षणकर्ता ने हर साक्ष्य , हर उस परिस्थिति से इनकार किया जो उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रस्तुत किए थे। उसके अनुसार उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उसने अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

31. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार पुनरीक्षण स्वीकार किए जाने के बाद, इस पर विस्तार से बहस की जा सकती है। परंतु न्यायालय यह स्पष्ट करता है कि पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मामले में बहुत विस्तार से बहस की है, दस्तावेजों और साक्षियों के बयानों का संदर्भ दिया है।

32. धारा 100 (4) का अनुपालन न करने से विचारण दूषित नहीं होता है। पीडब्ल्यू 1 किशन सिंह भंडारी, एक लोक सेवक है, उन्होंने अकेले विवेचना नहीं की है, उनके साथ पीडब्ल्यू3 हेत राम ममगाईं, पीडब्ल्यू 4 गंभीर सिंह बिष्ट और पीडब्ल्यू 5 मनोज बड़थ्वालभी थे। उन्हें स्वतंत्र साक्षी कहा जा सकता है। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यू1 किशन सिंह भंडारी के अनुसार पीडब्ल्यू6 सोबन सिंह पंप पर सेल्समैन था और चाबी सतेय सिंह ने दी थी। उन्हें भी स्वतंत्र साक्षी कहा जा सकता है। इसलिए, यह तर्क किसी भी तरह से आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को दूषित नहीं करता है।

33. यह तर्क दिया जाता है कि नमूने 10 दिनों के भीतर भेजे जाने थे, परंतु यह साबित नहीं हुआ है कि इसे जांच के लिए कब भेजा गया था। परीक्षण के संबंध में रिपोर्ट संख्या क7 पीडब्ल्यू9 अनूप सिंह रावत द्वारा साबित की गई है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि यह 15.04.2015 को दिया गया था। पीडब्ल्यू9 अनूप सिंह रावत के अनुसार, दरअसल उनके एक सहयोगी के द्वारा जांच कराई गई थी। कागज़ संख्या 5क/56 न्यायालय के समक्ष है, जिसे वास्तव में प्रदर्शित नहीं किया गया है। परंतु, इसके आधार पर, जो कि एक आधिकारिक अभिलेख है, पीडब्ल्यू 9 अनूप सिंह रावत के अनुसार, उन्होंने रिपोर्ट दी है। यह तर्क दिया जाता है कि पेपर नंबर 5 क/ 56 साबित नहीं हुआ है; इसमें यह दर्ज नहीं है कि कथित

तौर पर भेजा गया नमूना हाई स्पीड डीजल का था। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि नमूने वास्तव में हाई स्पीड डीजल के थे। यह तर्क निश्चित रूप से तथ्यात्मक बिंदुओं पर है। यद्यपि, इसे इस प्रकृति का विधिक रूप देने का प्रयास किया गया है कि एक अस्वीकार्य या अप्रासंगिक साक्ष्य को विमर्श में रखा गया है। परंतु, ऐसा नहीं है। पीडब्ल्यू 9 अनूप सिंह रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वह पुष्टि करता है कि नमूना एचएसडी बीएस -3 विनिर्देश था। उन्होंने न्यायालय में यह बताने में निष्पक्षता बरती है कि, वास्तव में, विश्लेषण उनके सहयोगी द्वारा किया गया था। जांच रिपोर्ट 5क/56 साबित नहीं हुई थी, परंतु न्यायालय के समक्ष थी। यह उन कार्यों को अभिलेख करता है जो उपस्थिति, सिटेन इंडेक्स (सीआई), पोर पॉइंट (समर) और कूपर स्ट्रिप जंग -3 एचआर 1000 सी कार्य बिंदुओं के संदर्भ में किए गए थे। इन पहलुओं पर इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई है। केवल इसलिए कि पेपर नंबर 5क/56, जिसे पीडब्ल्यू 9 अनूप सिंह रावत द्वारा संदर्भित किया गया है, प्रदर्शित नहीं किया गया है, यह पीडब्ल्यू 9 अनूप सिंह रावत की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि, वास्तव में, यह निष्कर्ष निकालते समय कि नमूना हाई स्पीड डीजल- एचएसडी बीएस-III का था, अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की।

34. यह तर्क दिया जाता है कि साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में कुछ विरोधाभास रहे हैं। पीडब्ल्यू1 किशन सिंह भंडारी के बयान का हवाला दिया गया है। ये सभी पहलू तथ्यात्मक हैं। तथ्य का समवर्ती निष्कर्ष है। पुनरीक्षण में, यह नहीं हो सकता है और यहां तक कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि न्यायालय ने भी साक्षियों के बयानों का अवलोकन किया है। ऐसा कोई सारभूत विरोधाभास नहीं है, जो किसी भी तरह से आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को गलत, अवैध या अनुचित बना सकता है।

35. पीडब्ल्यू 10 के प्रदीप कुमार के बयान का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि वास्तव में नमूना कभी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया। न्यायालय के समक्ष सील नहीं थी। पीडब्ल्यू 10 प्रदीप कुमार के बयान का कुछ हिस्सा न्यायालय के समक्षपढ़ा गया है। यह सच है कि नमूने न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किए गए थे। परंतु, फिर यह आक्षेपित निर्णयों और आदेशों को कैसे प्रभावित करेगा?

36. पीडब्ल्यू-1 किशन सिंह भंडारी का स्पष्ट मामला है कि 23.03.2015 को जब्ती के बाद उन्होंने जिला मजिस्ट्रेट और आपूर्ति अधिकारी को एक रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने 24.03.2015 को जिला आपूर्ति अधिकारी को नमूने भेजे (प्रदर्श क2 में उल्लिखित) और उसके बाद, प्राथमिकी दर्ज की। पेपर नंबर 5क/56, जिसके आधार पर पीडब्ल्यू9 अनूप सिंह रावत द्वारा प्रदर्श क7 लिखा गया था, उसमे उल्लिखित है कि नमूने 03.04.2015 को प्राप्त हुए थे। यह भी दर्ज है कि नमूने 01.04.2015 को लिए गए थे। क्या इसका अर्थ यह है कि उसके नमूने 01.04.2015 को भेजे गए थे? यदि ऐसा है, तो यह नमूने लेने की तारीख से 10 दिनों के भीतर है (पेपर नंबर 5 क/ 66 अभिलेख पर है। यह पेपर साबित नहीं हुआ है। इसमें

लिखा है कि नमूने 01.04.2015 को जांच के लिए भेजे गए थे।) अन्यथा भी 10 दिनों के भीतर नमूने अग्रेषित नहीं करने से विचारण प्रभावित नहीं होता है।

37. न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता से जानना चाहा कि क्या पुनरीक्षणकर्ता ने कभी आवेदन किया कि किसी अन्य नमूने को विवेचना के लिए भेजा जा सकता है? क्या उन्होंने ऐसा कोई आवेदन दिया था? उत्तर नकारात्मक में है।

38. पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष की किसी भी कमी को पुनरीक्षणकर्ता पूरी नहीं कर सकता है। वास्तव में, अभियोजन में कोई कमी नहीं है। प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार नमूने दिनांक 03/04/2015 को प्राप्त हुए थे। पीडब्ल्यू9 अनूप सिंह रावत ने प्रयोगशाला में की गई विवेचना के आधार पर रिपोर्ट दी। जैसा कि कहा गया है, उससे ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहरा सके।

39. तथ्यों और प्रस्तुतियों की संपूर्णता पर विचार करने के उपरांत, इस न्यायालय का विचार है कि इस पुनरीक्षण में कोई सार नहीं है। तदनुसार, पुनरीक्षण प्रारम्भिक स्तर में ही निरस्त किए जाने योग्य है।

40. पुनरीक्षण को प्रारंभिक स्तर पर खारिज कर दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति रवींद्र मैठानी,) 17.10.2022